अटके मास्टर प्लान पर फोकस मानचित्र स्वीकृति बनाएंगे सरल

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : प्रदेश के कई शहरों में वर्षों से लंबित मास्टर प्लान और सरकारी आवासीय योजनाओं के लिए भूमि की कमी को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। इन दोनों मुद्दों पर विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। मास्टर प्लान को समयबद्ध रूप से फाइनल किया जाएगा। लैंड पूलिंग नीति के जरिए लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर रहेगा, ताकि आवास एवं शहरी विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आवास सचिव डा. आर. राजेश कुमार ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की समीक्षा बैठक में यह कहा।

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में आवास सचिव डा. आर. राजेश कुमार ने एमडीडीए की प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा

- **सरकारी आवासीय योजनाओं के लिए भूमि की कमी को दूर करना सरकार की प्राथमिकता**

की। पार्किंग निर्माण, पार्कों का विकास, आवासीय योजनाएं, बाजार पुनर्विकास और अन्य शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार के साथ गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया को लेकर अहम निर्देश दिए। कहा, मानचित्र स्वीकृति व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी व समयबद्ध बनाया जाए।